उत्तर प्रदेश में स्त्री शिक्षा का अनुशीलन

रमेश चन्द्र*

"सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन–जन का कल्याण करें"[1] के सर्वमान्य सिद्धान्त के लिए, शिक्षा एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही वह मूल उत्स है जहां से परिवर्तन के रास्ते खुलते हैं। इसीलिए शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का जरिया भी कहा जाता है हुसैन, तैयब (2007)।[2] शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है।[3] नवाचार शिक्षा के अन्तर्गत 'मीना मंच कार्यक्रम', 'व्यवसायिक जागरूकता कार्यक्रम', 'जीवन कौशल शिविर' आदि इसके अतिरिक्त एन.पी.ई.जी.ई.एल. (प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम) एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना जैसे विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के 680 शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े विकासखण्डों में संचालित है।[4]

उत्तर प्रदेश का परिचय एवं स्त्री शिक्षा– उत्तर प्रदेश $23^0 52'$ से $30^0 24'$ उत्तरी अक्षांश और $77^0 5'$ से $84^0 38'$ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल, उत्तर–पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण–पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं पूरब में बिहार स्थिति है। उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश को भौतिक (फिजिकली) और भूगर्भ (जियोलोजीकली) विज्ञान की दृष्टि से तीन प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता था। यथा–उत्तर में हिमालय क्षेत्र, मध्य में गंगा के मैदानी क्षेत्र और दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र। परंतु नये राज्य उत्तराखण्ड की स्थापना के उपरांत हिमालय क्षेत्र पूर्णतया अलग–थलग हो गया है। अब केवल भाबर और तराई के इलाके ही बचे हैं, जिन्हें उपहिमालयी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।[5] उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या (77.72 प्रतिशत, 2011) पर्यावरण और इसकी भौगोलिक स्थिति ने मिलकर ग्रामीण समाज एवं संस्कृति का विकास किया है। वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार इसकी जनसंख्या 19,95,81,477 है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किन्तु साक्षरता की दृष्टि से इसकी गणना भारत के पिछड़े राज्यों में की जाती है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 56.36 प्रतिशत लोग ही साक्षर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 68.8 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 42.2 प्रतिशत रही। इसी तरह वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 69.72 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष पुरुषों की साक्षरता दर 79.24 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 59.26 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 4.32 प्रतिशत कम है। एक दशक 2001 से 2011 के दौरान राज्य की साक्षरता दर में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यातव्य हो कि देश में साक्षरता की दृष्टि से 29वें स्थान पर है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश का 28वां तथा महिला साक्षरता की दृष्टि से 31वां स्थान है।[6] साक्षरता की दृष्टि से वर्ष 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाले पांच जिलों में गाजियाबाद 85.00 प्रतिशत, गौतम बुद्धनगर 82.20 प्रतिशत, कानपुर नगर 81.31 प्रतिशत, औरैया 80.25 प्रतिशत और इटावा 79.99 प्रतिशत है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले पांच जिलो में क्रमशः श्रावस्ती 49.13 प्रतिशत, बहराइच 51.10 प्रतिशत, बलरामपुर 51.76 प्रतिशत, बदायूँ 52.91 प्रतिशत और रामपुर 55.08 प्रतिशत 30 है। प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले पांच जिलों में श्रावस्ती 59.55 प्रतिशत, बहराइच 6.23 प्रतिशत, बलरामपुर 61.66 प्रतिशत, बदायूँ 62.39 प्रतिशत और रामपुर 63.10 प्रतिशत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले पांच जिलों में गाजियाबाद 81.42 प्रतिशत, कानपुर नगर 76. 89 प्रतिशत, लखनऊ 73.88 प्रतिशत, गौतमबुद्ध नगर 72.78 प्रतिशत और औरैया 71.97 प्रतिशत है। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले पांच जिलों में श्रावस्ती 37.07 प्रतिशत, बहराइच 40.76 प्रतिशत, बलरामपुर 40.92 प्रतिशत, बदायूं 41.76 प्रतिशत और रामपुर 46.19 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जनगणनाओं के आधार पर तालिका में स्पष्ट कर सकते है –

सारणी संख्या 1

उत्तर प्रदेश में साक्षरता–दर के आँकड़े, 1951–2011[7]

वर्ष	जनसंख्या	पुरुष	महिला	स्त्री–पुरुष में अन्तर
1951	12.02	19.17	4.07	15.1
1961	20.87	32.08	8.36	23.72
1971	23.99	35.01	11.23	23.78
1981	32.65	46.65	16.74	29.91
1991	41.60	54.82	26.31	28.51
2001	56.36	68.80	42.20	26.60
2011	69.72	79.24	59.26	19.98

***शोधछात्र, शिक्षाशास्त्र उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा धारवाड़–580 001**

तालिका संख्या 1 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1951 में साक्षरता दर 12.02 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 19.17 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 4.07 प्रतिशत थी। पुरुष और स्त्री साक्षरता का अन्तर 15.1 प्रतिशत था। इसी प्रकार वर्ष 1991 में कुल साक्षरता 41.60 प्रतिशत था, जिसमें पुरुष साक्षरता 54.82 प्रतिशत और महिला साक्षरता 26.31 प्रतिशत था, जबकि पुरुष और महिला साक्षरता का अन्तर 28.51 था। वर्ष 2001 में साक्षरता दर बढ़कर कर 56.36 प्रतिशत हो गयी, जिसमें पुरुष साक्षरता 68.8 प्रतिशत और महिला साक्षरतादर 42.2 प्रतिशत थी, जबकि दोनों का अन्तर 26.6 प्रतिशत था। इसी प्रकार वर्ष 2011 में कुल साक्षरता में वृद्धि हुई और बढ कर 69.72 प्रतिशत हो गई है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79. 24 प्रतिशत है और महिला साक्षरता दर 59.26 प्रतिशत है। जबकि पुरुष और महिला साक्षरता का अन्तर 19.98 प्रतिशत हुआ है। जो कि महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ रही है, चूंकि पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से काफी अधिक है, फिर भी महिलाओं में भी वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य आमतौर पर अपनी स्त्रियों के शैक्षिक, सामाजिक पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है। चुनावों के दौरान महिला मतदाताओं ने अपने अधिकारों का प्रयोग सदा ही बहुत कम किया। हालांकि राज्य के महानगरों में रहने वाले उच्च साक्षर स्त्रियों ने अपने अधिकारों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग किया है फिर भी शिक्षा अथवा आर्थिक विकास और स्त्रियों द्वारा मताधिकार के प्रयोग के बीच ऐसा ही सह सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं है।[8]

सारणी संख्या 2

उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं की संख्या (हजार में)[9]

वर्ष	माध्यमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय
2006–07	3937	2477	10866
2011–12	5425	5189	12758
2012–13	5466	5199	12760

उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बालिकाओं की संख्या (हजार में)[9]

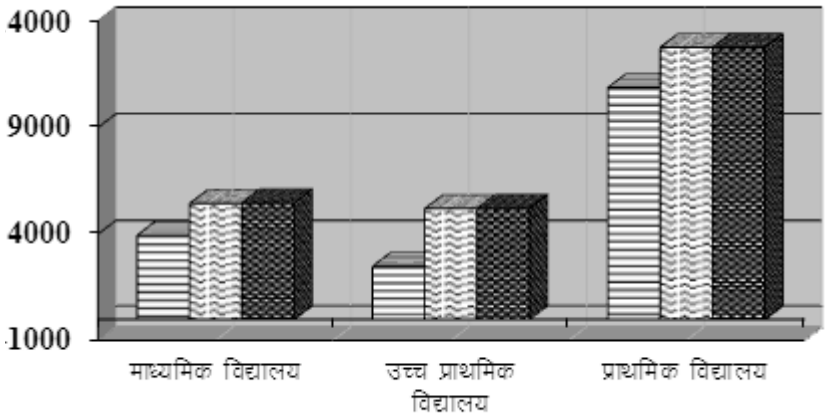

बेसिक शिक्षा – उत्तर प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से पिछडे विकास खण्डों में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6–8 की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 339 नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये जिसके फलस्वरूप बालिकाओं को कक्षा 6–8 की आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हुयी। कुल 454 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को क्रियाशील बनाया गया, जिनमे लगभग 41000 बालिकाये पंजीकृत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयो की बालिकाओं को स्कूल बैग वितरित किये गये, जिससे प्रति वर्ष लगभग 16.50 लाख बालिकायें लाभान्वित हुयी।

माध्यमिक शिक्षा – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बी.पबी. एल. कार्ड धारकों की बालिकाओ को शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 'सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना' 20 जनवरी, 2009 से प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 एव 2009–10 में क्रमशः 86,686 एवं 170527 छात्रायें लाभान्वित की गयी।[11] समाज के कामकाजी एव कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा मे लाने हेतु दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था हेतु स्थापित पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के स्थान पर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–27 वर्ष 2008 द्वारा की गयी। एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड

की दूसरी न्याय पंचायत में वर्ष 2007–08 मे 12 तथा 2008–09 में 15 कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना निजी प्रबन्ध तत्र के सहयोग से की गयी।

उच्च शिक्षा – दिल्ली के नजदीक नव सृजित जिला गौतमबुद्धनगर में 511 एकड़ के विशाल क्षेत्र मे विश्व–स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना। इस विश्वविद्यालय मे अनुसूचित जाति/जनजाति एव आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछडा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को शुल्क मे 50 प्रतिशत तक छूट देने की व्यवस्था तथा मेधावी बी.पी.एल. छात्र/छात्राओ के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत राजकीय व्यय पर विदेशो में उन्नत उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। छत्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर मे सावित्री बाई फुले महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हुआ।

व्यावसायिक शिक्षा – प्रदेश के नवयुवकों/नवयुवतियों को बडें पैमाने पर औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र मे रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का भरपूर लाभ दिलाने के उद्देश्य से व्यावसायिक एव प्राविधिक शिक्षा विभाग से पृथक कर व्यावसायिक शिक्षा विभाग का सृजन। पूरे उत्तर प्रदेश मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बी.पी.एल. परिवार की बालिकाओ द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने पर सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के अतर्गत एक साइकिल एवं रु. 25,000 प्रदान किये जाने की नयी योजना लाग की गयी।[12]

प्राविधिक शिक्षा–माध्यमिक शिक्षा विभाग के पैटर्न पर प्राविधिक शिक्षा विभाग मे भी 'सावित्री बाई फुले बालिका कल्याण योजना' लाग की गयी है।[13]

सन्दर्भ :

1 भारत 2010, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली.

2 हुसैन, तैयब (2007), शिक्षा परिदृष्य, शिक्षा विमर्श, नवम्बर–दिसम्बर, पृ. 39.

3 रमन, बिहारी लाल (2010), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ, पृ. 12.

4 उ. प्र. में बालिका शिक्षा की ओर बढ़ते कदम, मुक्ताकाश, उत्तर प्रदेश, त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 1, क 1, पृ. 2

5 झा, सुबोधनाथ (2009), **उत्तर प्रदेश देश और लोग**, अनुवाद, बनवारी लाल, नेशनल बुक ट्रस्ट, पृ. 1–2.

6 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, आगरा

7 भारत की जनगणना वर्ष 2011; उत्तर प्रदेश 2009 सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ.

8 उत्तर प्रदेश विधानसभा स्वर्ण जयंती स्मारिका, विधानसभा सचिवालय लखनऊ

9 सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश (2013), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 248.

10 उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार की जन–आस्था एवं विश्वास के तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, पृ. 53

11 उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार की जन–आस्था एवं विश्वास के तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, पृ. 54

12 उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार की जन–आस्था एवं विश्वास के तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, पृ. 58

13 उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार की जन–आस्था एवं विश्वास के तीन वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, पृ. 59.